IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका एवं क्वाड का गठन : एक विश्लेषनात्मक अध्ययन

डॉ.नेहा निरंजन
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान एवम् लोक प्रशासन विभाग
डॉ.हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश,इंडिया

सारांश :–

हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद–प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं। विश्व के बदलते भू–राजनीतिक परिपेक्ष्य में हिंद–प्रशांत क्षेत्र विश्व की विभिन्न महाशक्तियों के मध्य कूटनीतिक संघर्ष का नया मंच बना हुआ है। ऐसे में क्वाड के गठन का लक्ष्य ''हिंद–प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, समृद्ध और मुक्त बनाना है'', किंतु इसका मुख्य लक्ष्य 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के माध्यम से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी वर्चस्व को नियंत्रित करना भी है। हालाँकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है, भारत के लिये इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है। अतः इस क्षत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना इस शोध पत्र का प्रमुख्य उद्देश्य है ।

Key Words– हिंद–प्रशांत क्षेत्र, 'फ्री और ओपन इंडो–पैसिफिक', 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड', Quadrilateral Security Dialogue (QSD),, सागरमाला परियोजना, ब्लू इकॉनमी, सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन'

प्रस्तावना–

विश्व के बदलते भू–राजनीतिक परिपेक्ष्य में हिंद–प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक संघर्ष का नया मंच बना हुआ है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थितियां बहुध्रुवीयता के उभरने और शक्ति के पुनर्संतुलन की ओर इशारा करती हैं। आज यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक–आर्थिक अवस्थिति के कारण महत्त्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार के 75 प्रतिशत वस्तुओं एवम् सेवाओं का आयात–निर्यात इसी क्षेत्र से होता है, हिंद–प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। विश्व जीडीपी के 60 प्रतिशत का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापार (प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद) की दृष्टि से समस्त देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं, जो विश्व की कुल आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा है। इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं जिस कारण से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ इस क्षेत्र में सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएँ एवम् प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भू–आर्थिक प्रतिस्पद्धा में लगी हुई है।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र **(Indo-Pacific Region)**

हिंद महासागर (Indian Ocean) और प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद–प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं एवं विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को 'इंडो–पैसिफिक देश' कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीकी तट, हिंद महासागर तथा पश्चिमी एवं मध्य प्रशांत महासागर मिलकर हिंद–प्रशांत क्षेत्र बनाते हैं। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का भौगोलिक प्रसार अभी तक सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग हितधारकों ने इसे अलग–अलग तरह से मान्यता दी है। उदाहरण के लिये अमेरिका के लिये यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो कि यूएस इंडो–पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा है, जबकि भारत के लिये इसमें पूरा हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर शामिल है। बदलते परिपेक्ष्य में वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की कुंजी हिंद–प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है। इसके अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यहाँ आसियान के देश तथा चीन के मध्य लगातार विवाद चलता है। वही दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मलक्का का जलडमरूमध्य है जो रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूण है। गुआन आइलैंड, मार्शल आइलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लाल सागर, गल्फ ऑफ अदेन, पर्शियन गल्फ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ से भारत का तेल व्यापार होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेशेल्स और मालदीव भी इसी क्षेत्र में आते हैं इस प्रकार यह क्षेत्र रणनीतिक तथा व्यापारिक दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है।

वर्तमान में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र विश्व में आर्थिक विकास के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विश्व की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ यथा– अमेरिका, चीन, जापान और भारत इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि इस क्षेत्र की महत्ता को काफी अधिक बढ़ा देते हैं। यह क्षेत्र या तो विश्व के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले एक इंजन के तौर पर कार्य कर सकता है या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था के विध्वंसक के रूप में भी कार्य कर सकता है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में अनिवार्य भूमिका अदा कर सकता है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश (चीन), सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश (भारत) और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल राज्य (इंडोनेशिया) शामिल हैं, जिसके कारण यह देश भू–राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया की दस सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से सात इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में शामिल हैं, यही कारण है कि अमेरिका के मतानुसार, 'इंडो–पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका के भविष्य के लिये सबस अधिक परिणामी क्षेत्र है।'

पिछले दो दशको से इस क्षेत्र में चीन की सरकार अपनी नीतियों को वैश्विक आयाम देने का प्रयास कर रही है, जहा वन बेल्ट वन रोड नीति (Belt & Road Initiative) के क्रियान्वयन के एक प्रमुख घटक के रूप में चीन के लिये हिंद–प्रशांत क्षेत्र का विशेष महत्व है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका (USA) ने भी हिंद–प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, ताकि वह चीन के प्रसार को कम कर सके और अमेरिकी हितों को साध सके। अमेरिका और चीन के साथ ही भारत, जापान, आसियान देश (ASEAN) तथा फ्राँस भी अपनी भूमिका इस

क्षेत्र में बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रों की नीतियों ने इस क्षेत्र को विश्व राजनीति के पटल पर ला दिया है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ समुद्री सुरक्षा और सहयोग का महत्त्व बढ़ा है। विभिन्न देशों के संयुक्त वक्तव्य एवं संगठनों के घोषणा–पत्रों में समुद्री समझौतों को लेकर उच्च प्राथमिकता देखी जा सकती है। अमेरिका की हिन्द प्रशांत पर एक रिपोर्ट (US Indo-Pacific Strategy Report) में साझेदारी पर बल देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका नें चीन की नीतियों की आलोचना करते हुए उसको प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना है। साथ ही इस रिपोर्ट में 'नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्डर' (Rules-based International Order) तथा 'फ्री और ओपन इंडो–पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) क्षेत्र की वकालत की गई है। ट्रंप की हिंद–प्रशांत नीति उनके पूर्ववर्ती ओबामा की एशिया केंद्रित नीति का ही नया रूप है। एक अनुमान के अनुसार, चीन 2027 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह स्थिति अमेरिका के लिये चिंता पैदा कर सकती है। इंडोनेशिया भी आर्थिक रूप से मजबूत देश बनकर उभरा है तथा इस क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका तलाश रहा है। साथ ही वह अमेरिका की FOIP (Free and Open Indo-pacific) तथा चीन की (Belt and Road Initiative) का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, लेकिन इंडोनेशिया इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है कि अपने बल पर इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ज्ञात हो कि इंडोनेशिया आसियान संगठन का प्रमुख सदस्य देश है। अतः आसियान संगठन की भूमिका को हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिये महत्त्वपूर्ण बनाकर वह अपने हित संवर्द्धन का प्रयास कर रहा है। चीन भी अपने 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने के लिये दुनिया के विभिन्न देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। सर्वविदित है कि उसकी इस पहल का उद्देश्य इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी है। उदाहरण के लिये चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का प्रमुख हितधारक है और हाल ही में श्रीलंका सरकार ने हंबनटोटा पोर्ट को चीन के हाथों बेच दिया है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र को 'मुक्त एवं स्वतंत्र' क्षेत्र बनाने के लिये ट्रंप प्रशासन भारत–जापान संबंधों के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है क्योकि जापान ने हिंद–प्रशांत खासकर भारत के पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र में काफी निवेश किया है।

आजादी के बाद से ही भारत पूरी दुनिया में आदर्शवादी और लोकतांत्रित मूल्यों का समर्थन करने वाला एक प्रमुख देश रहा है, जिसने गुटनिरपेक्ष रहकर अपना विकास करने की योजना के साथ काम शुरू किया। 1970 के दशक में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदालन का नेतृत्व किया और 'नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' का मॉडल भी दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन भारत के लिए परिणाम सीमित ही रहे। शीत युद्ध खत्म होने के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद यह तय हो गया कि अमेरिका ही असली सुपरपावर है भारत को धीरे–धीरे लगने लगा कि आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा और फिर भारत ने विकास की गति को बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों के साथ हाथ मिलाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने विकास के लिए इतने प्रतिबंध बना रखे थे, कि भारत के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत के विकास के रास्ते में कई कांटे बिछा रखे थे। खासकर कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका लगातार भारत को परेशान करता था तो परमाणु कार्यक्रम चलाने पर भारत के सामने अमेरिकी प्रतिबंध का डर था। लिहाजा भारत ने अपने प्रमुख दोस्त रूस के साथ मिलकर ब्रिक्स (BRICS) की स्थापना की। जिसमें चीन को शामिल होने के लिए भारत ने ही मनाया था, ताकि अमेरिका के विरोध को नियंत्रित किया जा सके और विश्व में कई ध्रुवों का निर्माण हो सके। भारत ने इसके लिए रूस और चीन का समर्थन किया लेकिन, जब जॉर्ज बुश ने अमेरिका की सत्ता संभाली तो कश्मीर मुद्दे के साथ साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका के रूख मे परिवर्तन आना शुरू हो गया। तब अमेरिका को समझ में आने लगा कि एशिया में पाकिस्तान को सहयोग कर वो चीन को रोक नहीं सकता है, लिहाजा उसने अपनी नीति बदलते हुए भारत की मदद करने का फैसला लिया और यहीं से भारत और चीन के संबंध में फिर से तनाव आने शुरू हो गये। 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड की अवधारणा प्रस्तुत की, लेकिन चीन के दवाब में ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद इसका गठन टाल दिया गया था। पुनः 2012 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर एक 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' स्थापित करने के लिए विचार

प्रस्तुत किया गया और फिर नवंबर 2017 में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्वाड समूह की स्थापना की गई और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहल इसकी बैठक का आयोजन किया गया।

क्वाड (QUAD) की स्थापना –

क्वाड को 'स्वतंत्र, खुले और समृद्ध' हिंद–प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये चार देशों के साझा उद्देश्य के रूप में पहचाना जाता है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त रूप से अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। क्वाड' को Quadrilateral Security Dialogue (QSD) कहा जाता है। जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध–नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना के आदान–प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा विकसित किया गया है। मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रो जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। 13 वीं ईस्ट एशिया सम्मिट के दौरान ही क्वाड सम्मेलन का भी आयाजन किया गया था। यह क्वाड सम्मेलन मुख्यतः इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं एवं समुद्री सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित था। एक संकल्प के रूप में 'क्वाड' का गठन समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिये भी किया गया है। लगभग एक दशक निष्क्रिय रहे इस समूह को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया।

उद्देश्य–

वर्तमान में इसका लक्ष्य है–'हिंद–प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, समृद्ध और मुक्त बनाना, किंतु इसका म,ख्य लक्ष्य बेल्ट रोड पहल के माध्यम से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीनी दबदबे को नियंत्रित करना भी है।

उल्लेखनीय है कि चीन अपनी OBOR के माध्यम से हिंद–प्रशांत सहित अन्य छोटे–छोटे देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड को 'नियम–आधारित आदेश' को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था, ताकि नेविगेशन एवं ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार एवं समुद्री सुरक्षा को सहयेाग के मुख्य तत्त्व के रूप में पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का सिद्धांत है कि यह क्षेत्र मुक्त और समावेशी बने जहाँ विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। चीन ने दक्षिण चीन सागर में आर्टिफीशियल आइलैंड्स तैयार करना शुरू किया है जिससे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देश नाखुश हैं तथा उनके द्वारा इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है अतः यहाँ क्वाड का उद्देश्य सुगम परिवहन, सुरक्षा एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

हिंद और प्रशांत महासागर से लगे हुए चार लोकतंत्र जिनकी सोच एक जैसी मानी जाती है, जो साथ–साथ आगे बढ़ सकते हैं, और एक भू–राजनैतिक इलाके का निर्माण करते हैं, इसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. हांलाकि मौजूदा समय में इसकी संरचना, कार्यो ,इरादों आर रणनीति के बारे में जवाब से ज्यादा सवाल हैं. इंडो–पैसिफिक पर चारों देशों का अपना नजरिया है जिसे साझा नजरिए के साथ मिलकर आगे बढाना हर देश के लिए चुनौतीपूर्ण है. इससे ये जरूरत पैदा हो गई है कि चार देशों के तालमेल के मकसद पर फिर से बहस की जाए. वास्तव में कामचलाऊ छोटे–छोटे यूनियन में बंटना, चारों देशों के बीच मेल–मिलाप की कमी जैसे मसलों ने इस ग्रुप के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं कि क्या ये कुछ ठोस नतीजे दे पाएगा या बस ऐसे ही अलग–अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों का फोरम बनकर रह जाएगा और एक दूसरा मुद्दा ये है कि क्या चार देशों का ये तालमेल इलाके में एक शक्तिशाली सुरक्षा ढांचा बनाने में सक्षम है? और अगर ये संभव है तो उसका आकार कैसा होगा? इस तरह के सवाल खड़े होने के पीछे दो कारण हैं. पहला, जहां एक तरफ देश 'फ्री एंड ओपन इंडो–पैसेफिक' के लिए वचनबद्ध हं तो दूसरे इनमें आपसी सामंजस्य अभी ढीला–ढाला है हालांकि, चारों देशों के बीच समुद्र में सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का मजबूत सहयोग हैं लेकिन एक इकाई के तौर पर इंडो–पैसेफिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कुछ ठोस कदम सामने नहीं आये है। अनौपचारिक वादा, चीन को लेकर कुछ सदस्य देशों की बढ़ती चिंता और ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के क्षेत्रीय संकल्पो को लेकर अस्पष्टता ने अभी तक कुछ ठोस नतीजे प्रस्तुत नहीं किये है। भारत ने समंदर में आने–जाने की आजादो के सिद्धांत पर जोर देकर, समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के

साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है.ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग बढ़ रहा है. इस इलाके में और ज्यादा औपचारिक सुरक्षा ढांचे का पक्षधर न होते हुए भी वो ये नहीं चाहता कि उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खास गुट के साथ हो जिसका असर उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े, और यही वो दुविधा है जिसके कारण चार देशों के समूह और हिंद प्रशांत पर भारत का नजरिया साफ नहीं हो पाया है। हिंद–प्रशांत और चार देशों के समूह को अलग–अलग करके देखने का भारत का कूटनीतिक नजरिया न सिर्फ पूरी स्थिति को अस्पष्ट करता है बल्कि एक ऐसे सुरक्षा ढांचे की जरूरत को बल देता है जो भू–राजनीतिक विखंडन के बजाय एक सिलसिलवार रणनीति की वकालत करता हो। हिंद–प्रशांत में भारत स्वायत्तता और सामंजस्य के बीच एक तालमेल बनाना चाहता है. हालांकि, ये चार देशों के समूह (चौकड़ी) को हिंद–प्रशांत से अलग देखता है, पर इसके साथ ये खतरा भी है कि क्षेत्रीय विखंडता के लिए एक सिलसिलेवार रणनीति बनाने का मौका हाथ से निकल जाए. भारत के उद्देश्य का एक सकारात्मक तर्क ये भी है कि हिंद–प्रशांत को एक सिलसिलेवार रणनीति के तौर पर देखा जाए न कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ बंटे हुए लक्ष्यों, साझेदारियों और गठबंधनों के तौर पर। चार देशों के ये समूह भारत को एक मौका देते है कि वो इलाके के मध्य में होने के नात दोनों छोर पर रणनीतिक आधार पर अपनी सुरक्षा जरूरतों को खाड़ी से लेकर मलाक्का के स्ट्रेट (जलडमरू मध्य) तक पुख्ता करे। 2018 के शांग्रिला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद–प्रशांत के मुद्दे पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि, 'भारत हिंद–प्रशांत क्षेत्र को एक रणनीति या सीमित सदस्यों के क्लब के रूप में नहीं देखता और न ही ऐसे गुट के तौर पर जो वर्चस्व चाहता है और ये तो किसी भी हाल में नहीं मानते हैं कि ये किसी देश के खिलाफ है.' प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि भारत की हिंद–प्रशांत नीति चीन को एक किनारे लगाने के लिए भी नहीं है, हिंद–प्रशांत को लेकर भारत की एक सकारात्मक सोच है, जिसमें ASEAN को केंद्र में रख कर दक्षिण पूर्व एशिया को क्षेत्र का अहम् इलाका माना गया है. भारत की परिभाषा के तहत हिंद–प्रशांत 'एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो हम सब को प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है। इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो इस क्षेत्र के भीतर आते हैं और बाहर के भी जिनकी यहां साझेदारी है। इस तरह भारत ने जानबूझकर 'समावेशी' शब्द जोड़कर हिंद–प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है। भारत की परिभाषा में जिस तरह से 'सबको' शब्द शामिल किया गया है, वो सीधे तौर पर चार देशों के समूह के चीन विरोधी लक्ष्य को कमजोर करता है. ऐसा करने के पीछे की नीयत कहीं न कहीं, भारत को इस क्षेत्र में नौपरिवहन में सहूलियत दिलवाने के साथ ही बड़ी शक्तियों के साथ किसी तरह की दुश्मनी न मोल लेनी पड़े उसे ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इस क्वॉड को दोबारा खड़ा ही स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत के कथन पर हुआ है न कि क्षेत्र व्यापी समावेश के लिए. इस पूरे कथन के निशाने पर चीन है क्योंकि उसका भारी सैन्यीकरण, दक्षिण चीन सागर में दावों और हिंद महासागर में नौसेना की रणनीतिक चौकियों को क्षेत्र को अस्थिर करने की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि, इकाई के तौर पर चार देशों का ये क्वॉड या चौकड़ी चीन के साथ संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत ने हिंद–प्रशांत में चीन के संदर्भ में अभी अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया है. फिलहाल वो चौकड़ी का हिस्सा है जो क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख पर लगाम लगाने के लिए नियमबद्ध व्यवस्था का हिमायती है और साथ ही एक ऐसे समावेशी क्षेत्र की भी बात कर रहा है जो किसी देश के खिलाफ नहीं है। फिर भी समावेश की सीमाओं को भारत ने परिभाषित नहीं किया है। इससे ये साबित होता है कि हिंद–प्रशांत पर भारत की सोच चोन पर लगाम लगाना नहीं बल्कि क्वाड की तरफ उसका झुकाव साझा सिद्धांतों की तरफ प्रतिबद्धता है।

क्वाड में भारत की भूमिका–

दक्षिण एशिया के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े बाजारों में भारत का प्रमुख स्थान है और हाल के सालों में स्वास्थ्य, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। अमेरिका भी क्वाड की संभावनों को सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि 'फाइव आइज' में भी भारत को शामिल करना चाहता है, ताकि क्वाड को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही अमेरिका के प्रयास पर कोविड–19 संकट से निपटने के लिए क्वाड प्लस संवाद की भी शुरूआत की

गई, जिसमें ब्राजील, इजरायल, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को शामिल किया गया। अब ब्रिटेन द्वारा भारत समेत विश्व के 10 लोकतांत्रित देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने पर विचार किया जा रहा, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करते हुए, सभी देशों के सामूहिक योगदान के जरिए एक सुरक्षित 5G नेटवर्क का निर्माण करना है। वहीं, भारत द्वारा चीन पर निर्भरता कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।

भारत का लक्ष्य चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों को देखते हुए हिंद महासागर में क्वाड देशों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसके रहते हुए चीन हिंद महासागर में किसी भी कीमत पर अपना पैर आगे नहीं बढ़ा सके। दरअसल, वैश्विक व्यापार के लिहाज से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी भी हिंद महासागर में भारत काफी मजबूत है। लेकिन, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा करने के बाद चीन की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर में काफी बढ़ चुकी है, लिहाजा क्वाड की मदद से भारत चीन को काफी आसानी से हिंद महासागर से दूर रख सकता है। वहीं, पिछले कुछ सालों में विश्व के कई देशों ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। वहीं, फ्रांस और जर्मनी भी हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा सभी देश मिलकर चीन को आसानी से रोक सकते हैं।

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका : –

वर्तमान के भू–राजनीतिक विश्व में 'हिंद प्रशांत' क्षेत्र का महत्व तेजी से बढा है। इस क्षेत्र में भारत के आसियान मित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध है, और इसने क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने का रास्ता भी तय किया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए अलग से इंडो–पेसिफिक विभाग की स्थापना की है। ओशिनिया विभाग भी इसी भू–क्षेत्र को आधारित कर बनाया गया है। भारत के लिए हिंद प्रशांत वह विशाल समुद्री क्षेत्र है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तटों तक फैला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिये अलगाव की स्थिति थी। लेकिन अब हिंद–प्रशांत क्षेत्र के लिये भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है। सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीति को मूर्तरूप देने के लिये सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। इस तरह भारत न सिर्फ हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा बल्कि ब्लू इकॉनमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा।

सागरमाला परियोजना)Sagarmala Project)

सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत 25 मार्च, 2015 को की गई थी। इसे भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्रों, 14,500 किलोमीटर संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीतिक स्थानों के दोहन के उद्देश्य से सरकार ने महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तैयार किया है।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy)

नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सागरों अथवा महासागरों से जुडी हो। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत रणनीतिक स्थातन पर है और वह अपने सतत् समावेशी और जन केंद्रित रूप में नीली अर्थव्यावस्था के विकास को स्वीकृति देता हैं। भारत द्वारा अपनी महत्वकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 600 से अधिक परियोजनाएँ चिह्नित की गई हैं और इनमें वर्ष 2020 तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए (120 बिलियन डॉलर) के निवेश का प्रावधान है। भारत अपने मैरीटाइम ढाँचे के साथ–साथ अंतर्देशीय जलमार्गों तथा महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से तटीय जहाजरानी (Coastal Shipment) को विकसित कर रहा है।

ब्लू इकॉनमी पर बल देने तथा हिंद–प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए ही नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों को आमंत्रित किया, इतना ही नहीं भारतीय प्रधानमंत्री नें अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये मालदीव और श्रीलंका को चुना। भारत द्वारा हिंद–प्रशांत क्षेत्र को लेकर किये गए प्रयास इस

क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती विदेश नीति को प्रदर्शित करते हैं तथा इस क्षेत्र के महत्त्व को भी इंगित करते हैं।

समुद्री हितों को लेकर भारत को इस क्षेत्र में और अधिक सक्रिय रूप से विदेशनीति को गति देने की आवश्यकता है, जिससे वह इस क्षेत्र में विकसित हो रहे रणनीतिक परिपेक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभा सके अतः भारत को सागरमाला (SAGAR) पहल पर बल देना होगा और इसके लिये एक ऐसे ढाँचे का निर्माण करना होगा जिससे नीति का उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। भारत द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और इसके लिये भारत को सागरमाला परियोजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परियोजना अवसंरचना को तटीय भागों में सुदृढ़ करेगी जिससे विनिर्माण, व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी ओर विश्व के लगभग सभी देश समुद्र में स्वतंत्र नौ–परिवहन को लेकर एक मत हैं लेकिन विभिन्न देशों में नौ–परिवहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसका कारण कई देशों के कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून 1982 (International Maritime Law-IML) से भिन्न होना है। इस विषय पर भारत अन्य देशों के मध्य मतभेदों को समाप्त करने और एक निश्चित परिभाषा पर सहमत होने के लिये नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। भारत का IML के पालन करने का रिकॉर्ड और समुद्री शक्ति के रूप में इसकी विश्वसनीयता, इसे इस तरह के प्रयास का नेतृत्व करने के लिये एक आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। साथ ही भारत को चाहिए कि वह हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुँच में वृद्धि करे। परिचालन द्वारा भारत अपनी उपस्थिति को इस क्षेत्र में मजबूती से दर्ज करा सकता है। इस क्षेत्र में भारत के जापान जैसे सहयोगी पहल से ही मौजूद हैं, जो भारत को आवश्यकता के समय सुप्रचालन (logistic) आधार उपलब्ध करा सकते हैं। यह इस क्षेत्र में भारत के दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करेगा, साथ ही इस क्षेत्र की स्थिरता को भी मजबूतो प्रदान करेगा।

दूसरी ओर पूर्व में भारत के रूस जैसे मित्र राष्ट्र भी है, भले ही इस समय भारत–अमेरिका संबंधो में घनिष्ठता है और रूस एवं चीन सम्बन्ध प्रगाण हो रहे है लेकिन इन अन्तर्विरोधो के बावजूद दिसम्बर 2020 में रुसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की दोनों देशो के मध्य 28 समझोतों पर हस्ताक्षर हुए एवं 2020 में भारत–रूस व्यापार 9.31 बिलियन डॉलर का रहा। इस व्यापार को 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत से रूस तक आने जाने का ईरान,पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के गणतंत्रो से थल मार्ग एवं चेन्नई से व्लादिवोस्तक तक जल मार्ग के उपलब्ध करवाने के लिए दोनों देशो को चिंतन एवं गहन कूटनीति का सहारा लेना होगा। भारत द्वारा सागरमाला परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं को भी आरंभ किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बंदरगाहों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, तटों के करीब रहने वाले लोगों का सामाजिक–आर्थिक विकास, निवेश तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नई नौकरियां के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है। इन परियोजनाओं को लागू करते समय इनके प्रभावों और अवधि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि निश्चित समय में परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर क्षमता निर्माण एवं अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार को हिंद–प्रशांत क्षेत्र को समर्पित एक अध्ययन केंद्र के निर्माण की संभावना पर भी विचार करना चाहिये। यदि संभव हो तो ऐसे केंद्र की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप में हो सकती है जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये। ऐसे केंद्र के निर्माण के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है जो संसाधन के साथ–साथ विशेषज्ञता के संदर्भ में भी उपयोगी होगा। भारत की हिंद–प्रशांत रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में सिंगापुर के एक भाषण में सागर (एसएजीआर) सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री ने इसे "सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन' के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। यह आकांक्षा इस क्षेत्र में 'एंड–टू–एंड सप्लाई चेन' हासिल करने पर निर्भर करती है। इस विचार में किसी एक देश पर निर्भरता न होकर सभी लाभार्थियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है। भारत के लिए हिंद–प्रशांत का विचार ऐसा है, जिसमें नियमों का पालन, नेवीगेशन की स्वतंत्रता, खुले संपर्क और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान हो। भारत ने अपने इस सिद्धांत पर विषयगत और भौगोलिक पहल के माध्यम से काम भी किया है। इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता बनकर सुरक्षा और नेविगेशन

की स्वतंत्रता को मजबूत करने की मांग की है। उपकरण, प्रशिक्षण और अभ्यास में पूरे क्षेत्र के देशों के साथ भागीदारी करते हुए मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में भारत ने न केवल मजबूत क्षमताओं का निर्माण किया है, बल्कि खुद को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में भी स्थापित किया है। 2019 में भारत और यू.के. द्वारा कोलीशन फॉर डिजास्टर रेसिलियेन्ट इंफ्रास्ट्रकचर (सीडीआरआई) गठबंधन किया गया था। कोविड–19 के शुरूआत में भी भारत ने रैपिड रेस्पोन्स मेडिकल टीम्स, खाद्यान्न, कोविड सामग्री आदि के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों को बहुत सहयोग किया है। हिंद–प्रशांत के भूगोल को संभवतः अर्ध–वृत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सबसे नजदीकी अर्ध– वृत्त में हमारे निकटतक पड़ोसी देश हैं। ये सभी दक्षिण एशियाई देश हैं, जिन्होंने भारत के साथ हिंद महासागर के जल के अलावा सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की साझेदारी भी की है। बाहरी वृत्त पश्चिम और दक्षिणपूर्वी एशिया में खाड़ी देशों और आसियान देशों को समाहित करता है। एक अर्थ में यह भी हमारे प्राचीन समुद्री संबंधों की फिर से स्थापना है। इसमें ऊर्जा और निवेश प्रवाह, श्रम और

कौशल, व्यापार और व्यवसाय आदि भी जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए, भारत ने उन देशों के साथ साझेदारी की है, जिनके अवसर, सरोकार और हित हमारे साथ हैं। इसमें पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीप समूह तथा अफ्रीका के पूर्व तटीय देश हैं। क्वाड, भारत जापान–अमेरिका, भारत–फ्रांस–आस्ट्रेलिया और भारत–इंडोनेशिया–आस्ट्रेलिया जैसे त्रिकोण और चतुर्भुज बने हुए हैं। इन सब सहयोग संबंधों के बीच आसियान देशों की साझेदारी केंद्रीय भूमिका रखती है। आसियन एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जहा विभिन्न हित आपस में मिल–बैठकर बातचीत कर सकते हैं, और मतभेदों को तर्कसंगत बना सकते हैं। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा बैठक में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला बनाने पर भी चर्चा की गई। समुद्री सुरक्षा सहयोग के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), पारस्परिक रसद समर्थन और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण देशों की क्षमता निर्माण में सहायता जैसे मुद्दे शामिल किये गए। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोनावायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है।

हिंद–प्रशांत रणनीति की प्रासंगिकता :–

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच समूहों के गठन से व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से द्विपक्षीय तथा व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे साथ ही पीपुल–टू–पीपुल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल तथा भारत की 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का लक्ष्य शेष विश्व में इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी का विकास करना है। अतः इन दोनों पहलों को इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में विकास हेतु एकजुट होने की जरूरत है। भारत और चीन को इस क्षेत्र में शत्रुता त्यागकर शांति और समरसता लाने हेतु सहयोग करना चाहिये। इससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने को बल मिलेगा तथा क्षेत्रीय विवादों का समाधान हो सकेगा। चीन को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं तोड़ने की नीति पर चलना होगा ताकि छोटे दशों पर चीन की विस्तारवादी नीति का प्रभाव न दिखाई दे। आपसी बातचीत तथा कूटनीतिक संबंध से हिंद–प्रशांत रणनीति भविष्य में सफल हो सकती है। इस तरह के प्रयास से ही हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सकती है। आवश्यक है कि भारत को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद चीन के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करने का प्रयास करना चाहिये, ताकि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में यथासंभव शांति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जापान और भारत के बीच सुगम रिश्ता भी स्थिर और शांत हिंद–प्रशांत क्षेत्र तथा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला हेतु प्रमुख घटक रहेंगे। भारत को इस समय आसियान केंद्रित विकास एजेंडे और क्वाड केंद्रित सुरक्षा एजेंडे के बीच विकल्प बनाने की जरूरत नहीं है।

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ : –

- इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की अभी तक कोई स्पष्ट परिभाषा मौजूद नहीं है और सभी देश अपने–अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रख कर इसे परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- जानकारों का मानना है कि विगत कुछ वर्षों में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता का एक नया केंद्र बिंदु बन गया है, इस क्षेत्र की दो बडो अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका और चीन) के बीच व्यापार युद्ध तथा तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा के कारण इस क्षेत्र के अन्य देशों और संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
- इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के कई देश खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया आदि भारत की भूमिका को इस क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। ये सभी देश दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिये भारत को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हालाँकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है, भारत के लिये इंडो–पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है।भारत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सभी देशों और उन सभी देशों को इंडो–पैसिफिक क्षेत्र को परिभाषा में शामिल करता है, जिनके हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जबकि भारत, इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की अमेरिकी परिभाषा का अनुपालन नहीं करता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य चीन के प्रभाव को सीमित करना अथवा समाप्त करना है।

निष्कर्ष

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से वैश्विक महत्व के केंद्र के रूप में उभर रहा ह। यदि इस क्षेत्र के हितधारक एक खुले, नियम–आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिये कार्य नहीं करते हं, तो सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती रहेगी, जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ना संभावित है। आसियान जैसे समूहों को सामूहिक रूप से चीन से संपर्क स्थापित करना होगा। चीन की आक्रामकता और ऋण जाल (Debt Trap) कूटनीति, जो संप्रभुता को प्रभावित करती है, भारतीय कूटनीति की परीक्षा ले रही है। वर्तमान में जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा ह। संपूर्ण इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हाल के वर्षों में हिंद–प्रशांत क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्रबिंदु बनकर उभरा है। आर्थिक महत्ता की वृद्धि ने इस क्षेत्र को भू–राजनीति के मंच पर ला दिया है। इसी आधार पर विभिन्न राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिये इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के हितों की दृष्टि से आवश्यक है कि भारत भी हिंद–प्रशांत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। आर्थिक रूप से मजबूत किंतु विनम्र (benign) राष्ट्र की छवि भारत के लिये सहयोगी बनाने में प्रायः सहायक ही है, इन सहयोगियों के साथ चलकर भारत इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति को प्राप्त कर सकता है तथा चीन की प्रसार की नीति के बावजूद अपने हितों को पूरा करने में सफल हो सकता है।

सन्दर्भ सूची –

- https://www.orfonline.org/tags/
- https://www.orfonline.org/hindi/research/india-in-the-indo-pacific-china-covid-19/
- **श्याम सरन, हिंद–प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और भारत की भूमिका,**December 02, 2020
  https://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=173992
- डॉ विवेक मिश्रा , इंडो–पैसिफिक का विकासः रूस का बढ़ता उपक्रम January 17] 2020
- भारतीय वैश्विक परिषद् ,सप्रू हाउस ,नई दिल्ली ''हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की भू–राजनीतिः एशियाई परिप्रेक्ष्य में' विषय पर चौथा (प्ट) एशियाई संबंध सम्मेलन'' पर इवेंट रिपोर्ट , 21-22 मार्च, 2013
) https://www.punjabkesari.in/national/news/india-america-relation-indo-pacific-region- (1337163
- Indo-Pacific Strategy Report'. *U.S. Department of Defense*. June 01, 2019. Available at: https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF. Accessed November 04, 2019.
- See:// https://diligentias.com/14th-east-asia-summit-is-being-held-in-bangkok-diligent-ias/, Accessed on September 17, 2020.
- **क्वाड' देशों का तीसरा सम्मेलन** (Third Meeting of the 'Quad' Countries), **द हिंदू** NOV 16 , 2018
- East Asia Summit, *Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government*, https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/eas/Pages/east-asia-summit-eas, Accessed on September 10, 2020.
- "13th India-Japan Foreign Ministers' Strategic Dialogue", *Ministry of External Affairs*, October 7, 2020, https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33100/13th_IndiaJapan_Foreign_Ministers_Strategic_Dialogue, Accessed on October 23, 2020.
- "Fact Sheet: Quad Summit", *White House*, March 12, 2021.
- Girish Luthra, "The Indo-Pacific Quest for the Quad's Spirit," ORF Issue Brief No. 473, July 2021, *Observer Research Foundation.* Jeff Smith, "The Quad 2.0: A Foundation for a Free and Open Indo–Pacific", *Heritage Foundation*, July 6, 2020,